नईदुनिया

भारत-कनाडा यूरेनियम सप्लाई समझौता, परमाणु ऊर्जा विस्तार को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कनाडा के साथ 2.6 अरब डॉलर के दीर्घकालिक यूरेनियम सप्लाई समझौते को भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वैश्विक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता भारत के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मजबूत करेगा, जिसके तहत देश 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहता है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में घरेलू स्तर पर यूरेनियम उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे में लंबे समय के लिए यूरेनियम आयात की व्यवस्था करना जरूरी हो जाता है।

रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि भारत में यूरेनियम का घरेलू उत्पादन कुल मांग से काफी कम रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि मौजूदा और भविष्य के परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए भारत को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसी कारण कनाडा के साथ दीर्घकालिक सप्लाई समझौता रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक कजाकिस्तान से भारत पिछले कुछ वर्षों से यूरेनियम का प्रमुख आयात करता रहा है। अब कनाडा के साथ हुआ यह समझौता भारत के लिए इस अहम ईंधन का एक और बड़ा स्रोत खोल देगा, जिससे देश के परमाणु रिएक्टरों को ऊर्जा मिल सकेगी।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दिसंबर 2025 में भारत की संसद ने नागरिक परमाणु ऊर्जा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पहली बार घरेलू और विदेशी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने, उनके मालिक बनने और संचालन करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले यह क्षेत्र पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था।

शेयर बाजार में भारी गिरावट सेंसेक्स 1,097 अंक लुढ़का

मुंबई। पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी गिरावट देखी गयी और बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,097 अंक (1.37 प्रतिशत) टूटकर 17 अप्रैल 2025 के बाद के निचले स्तर 78,918.90 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 315.45 अंक यानी 1.27 प्रतिशत गिरकर 24,450.45 अंक पर आ गया जो इसका 29 अगस्त 2025 के बाद का निचला स्तर है।

पिछले पांच कारोबारी दिवसों में से चार में शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट रही है जबकि गुरुवार को बड़ी तेजी देखी गयी। सेंसेक्स गुरुवार को 900 अंक चढ़ने के बावजूद पांच दिन में कुल 3,329.71 अंक (4.04 प्रतिशत) टूट चुका है। निफ्टी-50 भी पांच कारोबारी दिवस में 1,046.10 अंक (4.10 प्रतिशत) उतर चुका है। मझौली और छोटी कंपनियों पर आज अपेक्षाकृत कम दबाव रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.86 प्रतिशत गिर गया। स्मॉलकैप-100 सूचकांक में भी 0.24 प्रतिशत की गिरावट रही। बाजार में उथल-पुथल को मापने वाला इंडिया वीआईएक्स सूचकांक 11 से ऊपर रहा जो दिखता है कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है।

1,140 से ज्यादा टोल प्लाजा पर डे शिफ्ट में संभालेंगी जिम्मेदारी, बेहतर सेवा और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा

टोल प्लाजा पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, एनएचएआई ने 5,100 से अधिक महिला कर्मचारी तैनात कीं

नई दिल्ली। टोल संचालन में महिलाओं के सशक्तिकरण और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क पर 1,140 से अधिक टोल प्लाजा पर टोल बूथों के प्रबंधन के लिए दिन की पाली (डे शिफ्ट) के दौरान 5,100 से अधिक महिला कर्मचारियों को तैनात किया है। यह जानकारी शुक्रवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई।

मंत्रालय ने बताया कि अग्रिम पंक्ति की परिचालन भूमिकाओं में विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को तैनात करने का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। साथ ही, इसका लक्ष?य एक कुशल, सहानुभूतिपूर्ण और उपयोगकर्ता के अनुकूल वातावरण तैयार करना है, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर विवादों की संभावना को कम करना है।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह निर्णय विभिन्न पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श और चर्चा के बाद लिया गया है। इसमें टोल प्लाजा संचालक तथा प्रमुख उद्योग संगठनों जैसे नेशनल हाइवेज बिल्डर फेडरेशन (एनएचबीएफ), हाइवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचओएआई) और ऑल इंडिया यूजर फी कॉन्ट्रैक्टर्स फेडरेशन (एआईयूसीएफ) शामिल थे।

सभी टोल संचालकों ने टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह के लिए दिन की पाली में महिला कर्मचारियों की तैनाती पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। अब तक 5,100 से अधिक महिला टोल कर्मचारी तैनात की जा चुकी हैं और निकट भविष्य में और भी महिलाओं के जुड़ने की संभावना है।

बयान में आगे कहा गया कि एनएचएआई इस पहल के क्रियान?वयन की करीबी निगरानी करेगा, ताकि इसका सही अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना क्षेत्र में उनकी भागीदारी को मजबूत करेगी। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार सृजन को भी ब?ावा मिलेगा। इस पहल के तहत एनएचएआई तैनात महिला कर्मचारियों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के साथ विनम्र व्यवहार, आपातकालीन स्थितियों को संभालने, बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल और कुशल टोल प्लाजा संचालन बनाए रखने जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। यह संरचित क्षमता-निर्माण प्रयास एक सुरक्षित और और पेशेवर कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हुए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेगा। मंत्रालय के मुताबिक, अग्रिम पंक्ति की परिचालन भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत?साहित करके एनएएचआई का लक्ष?य लैंगिक समावेशिता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर सेवा वितरण में सुधार करना है।

सोना फिर 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे, चांदी की कीमत में भी आई कमी

नई दिल्ली । सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। इससे सोने का दाम फिर से 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 2.60 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,835 रुपए कम होकर 1,58,751 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,60,586 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

22 कैरेट सोने का दाम 1,47,097 रुपए प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,45,416 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 1,19,063 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,20,440 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखी गई है। चांदी का दाम 3,489 रुपए कम होकर 2,60,723 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,64,212 रुपए प्रति किलो था। वायदा बाजार में सोने और चांदी सपाट हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) सोने के 2 अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.05 प्रतिशत बढ़कर 1,59,757 रुपए और चांदी के 5 मई 2026 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 0.30 प्रतिशत बढ़कर 2,62,990 रुपए हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 0.28 प्रतिशत बढ़कर 5,093 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.58 प्रतिशत बढ़कर 82.62 डॉलर प्रति औंस हो गई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि एमसीएक्स पर सोना 1,59,500 रुपए से लेकर 1,60,000 रुपए के बीच मे एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और कॉमेक्स पर यह 5,100 डॉलर प्रति औंस के आसपास है।

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका

नई दिल्ली । कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में युद्ध कुछ दिनों तक जारी रहने से खाड़ी देशों के निर्यातकों को अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मेज्योर) घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे आपूर्ति रुक ??जाएगी और कुछ ही हफ्तों में तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमत 40 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) तक पहुंच जाएगी।

कतर के मंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा, जिन देशों ने अभी तक फोर्स मेज्योर घोषित नहीं किया है, हमें उम्मीद है कि स्थिति जारी रहने पर वे अगले कुछ दिनों में ऐसा करेंगे। खाड़ी क्षेत्र के सभी निर्यातकों को फोर्स मेज्योर घोषित करना होगा।

उन्होंने आगे कहा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें किसी न किसी बिंदु पर कानूनी रूप से उस दायित्व का भुगतान करना होगा, और यह उनकी पसंद है।

मंत्री ने कहा कि अगर टैंकर और अन्य जहाज जलडमरूमध्य से गुजरने में असमर्थ रहे तो कच्चे तेल की कीमतें दो से तीन सप्ताह के भीतर 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जबकि प्राकृतिक गैस की कीमतें चार गुना बढ़ सकती हैं।

ब्रेंट क्रूड वायदा में इस सप्ताह 20 प्रतिशत की तेजी आई है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शुक्रवार को ब्रेंट 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 89 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि डब्ल्यूटीआई 5 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 86 डॉलर पर पहुंच गया। दोनों बेंचमार्क अप्रैल 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

दुनिया में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कतर, इस सप्ताह ईरान के ड्रोन हमले में अपने रास लाफान एलएनजी प्लांट पर हुए हमले के बाद अप्रत्याशित आपातकाल (फोर्स मेज्योर) घोषित कर चुका है। यह संयंत्र देश का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट है और इसमें हुए नुकसान का आकलन करने के प्रयास जारी हैं।

मंत्री ने बताया कि हमले तुरंत बंद होने पर भी, रसद संबंधी बाधाओं के कारण सामान्य निर्यात परिचालन बहाल करने में हफ्तों से महीनों का समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि कतर के 128 एलएनजी वाहक जहाजों में से केवल छह या सात ही वर्तमान में माल लादने के लिए उपलब्ध हैं। कम से कम 10 जहाजों पर हमले की खबरों और बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम में भारी वृद्धि के बाद, शिपिंग कंपनियां इस क्षेत्र से जहाज भेजने में हिचकिचा रही हैं।

ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलों और ड्रोन से हमले करने और बहरीन में एक तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने के बाद तेल की कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है।

फोनपे का मर्चेंट नेटवर्क 47 मिलियन बिजनेस तक पहुंचा डीआरएचपी में मिली डायवर्सिफाइड मॉनेटाइजेशन की जानकारी

नई दिल्ली। फोनपे लिमिटेड अपने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की तैयारी कर रही है, उसके अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में मर्चेंट इकोसिस्टम के विशाल पैमाने और मॉनेटाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई है। फोनपे कोई मुफ्त सेवा नहीं है, बल्कि इसका मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 47 मिलियन व्यवसायों और लाखों फिजिकल पेमेंट डिवाइसों द्वारा संचालित एक अरबों रुपए के रेवेन्यू इंजन में विकसित हो चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि फोनपे ने लगभग पूरे भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बना ली है।

30 सितंबर, 2025 तक, फोनपे के पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 47.19 मिलियन तक पहुंच गई, जो भारत के सभी पिन कोडों के 98.61 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं। 31 मार्च, 2025 तक, यह आधार भारत की कुल ट्रेड और सर्विसेज मर्चेंट आबादी का 77 प्रतिशत से 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। मार्च 2025 में मंथली एक्टिव मर्चेंट्स की संख्या 11.31 मिलियन थी, जो देश के सभी एक्टिव यूपीआई मर्चेंट्स का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा था। मार्च 2023 में डेली एक्टिव मर्चेंट इंगेजमेंट 44.18 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 तक 60.77 प्रतिशत हो गई। फोनपे का फिजिकल फुटप्रिंट इसकी सदस्यता से होने वाली आय का एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में तैनात 9.19 मिलियन डिवाइस केवल भुगतान उपकरण से कहीं अधिक कार्य करते हैं; स्मार्टस्पीकर एक संचार माध्यम के रूप में काम करता है, जो व्यापारियों को व्यावसायिक अपडेट और अलर्ट प्रदान करता है। इस हार्डवेयर नेटवर्क का रखरखाव 25,657 टीम सदस्यों और 31,000 से अधिक नियुक्त एजेंटों की एक विशाल टीम द्वारा किया जाता है।

फरवरी में शाकाहारी थाली की कीमत स्थिर, मांसाहारी थाली 3 प्रतिशत हुई सस्ती

नई दिल्ली। क्रिसिल इंटेलिजेंस की आज जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में घर पर पकाई गई शाकाहारी थाली की कीमत में सालाना आधार पर कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में 3 प्रतिशत की गिरावट आई। रिपोर्ट में बताया गया कि फरवरी में आलू, प्याज और दालों की कीमत में कमी आने के बावजूद भी शाकाहारी थाली की कीमत यथावत रहने की वजह टमाटर की कीमत बढ़ना है।

अधिक आवक के कारण प्याज की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत की गिरावट आई। आलू की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि फसल कटाई के चरम पर पहुंच चुकी है और पिछले रबी सीजन के कोल्ड स्टोरेज स्टॉक की बिक्री जारी है। चालू वित्त वर्ष में अधिक ओपनिंग स्टॉक के कारण दालों की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की गिरावट आई।

रिपोर्ट में बताया गया कि घर पर थाली बनाने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित कच्चे माल की कीमतों के आधार पर की जाती है। मासिक बदलाव आम आदमी के खर्च पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मांसाहारी थाली की कीमत में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण ब्रॉयलर की कीमतों में वार्षिक आधार पर अनुमानित 7 प्रतिशत की कमी है। ब्रॉयलर की कीमतें कुल मांसाहारी थाली की लागत का 50 प्रतिशत होती है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुष्पन शर्मा ने कहा, टमाटर की कीमतों में उछाल का कारण रोपाई में देरी है, जिससे फसल के विकास और पैदावार पर असर पड़ा। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मंडियों में फसल की आवक में वार्षिक आधार पर 32 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निकट भविष्य में सब्जियों की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है। टमाटर की कीमतें अप्रैल के मध्य तक पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहने की संभावना है और फिर मौसमी आवक बढ़ने और बाजार में फसल चक्रों के बदलाव के साथ इनमें मजबूती आएगी।

शर्मा ने कहा, आलू की कीमतें मार्च-अप्रैल के दौरान, यानी आवक के चरम मौसम में, कम रहने की संभावना है, जबकि प्याज की कीमतों पर अगले दो से तीन महीनों में दबाव पड़ सकता है, जब तक कि निर्यात में मजबूत वृद्धि न हो। मध्य पूर्व में व्याप्त अनिश्चितताओं और संभावित व्यापारिक बाधाओं के कारण निकट भविष्य में बासमती चावल की मांग में नरमी आ सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। भारत के बासमती चावल निर्यात में ईरान का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत है और अन्य मध्य पूर्वी देशों का 55-60 प्रतिशत हिस्सा है, इसलिए निर्यातक संभावित रसद संबंधी चुनौतियों को लेकर सतर्क हैं।

स्किलिंग और स्टार्टअप नीति से उत्तर प्रदेश में इनोवेशन की नई लहर

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित स्किलिंग को बढ़ावा देने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। स्टार्टअप नीति और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के माध्यम से प्रदेश में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तैयारी जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि एआई और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएं। स्टार्टअप नीति, एआई स्किलिंग और तकनीकी निवेश के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे शहरों में स्टार्टअप गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को भी नई दिशा मिल रही है और युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में टेक्नोलॉजी-आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की लगभग 400 यूनिट्स सक्रिय हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 100 से अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन इन्क्यूबेटरों के माध्यम से युवाओं को अपने नवाचार और तकनीकी विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी वैश्विक तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से युवाओं को आधुनिक डिजिटल स्किल्स और एआई तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी तेजी से विस्तार कर रहा है। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 65 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रदेश एक बड़े विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। इससे स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र को भी नई ऊर्जा मिल रही है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से जुड़ी सप्लाई चेन में कई छोटे और मध्यम उद्योगों को नए अवसर मिल रहे हैं, जिससे रोजगार के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

युवाओं को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रदेश के 49 आईटीआई संस्थानों में एआई लैब स्थापित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्रों को एआई, डेटा एनालिटिक्स और उन्नत डिजिटल तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। आईटी और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते निवेश का असर निर्यात पर भी दिखाई दे रहा है।

प्रदेश से आईटी-आईटीईएस क्षेत्र का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वर्तमान में 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश तेजी से डिजिटल और तकनीकी नवाचार के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

भारत के 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 17 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीदः आईएमएफ

नई दिल्ली । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत के 2026 में वैश्विक वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 17 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आईएमएफ की शीर्ष 10 देशों की सूची में अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका से वैश्विक जीडीपी वृद्धि में लगभग 9.9 प्रतिशत योगदान का अनुमान है। इसके बाद इंडोनेशिया 3.8 प्रतिशत, तुर्किए 2.2 प्रतिशत, सऊदी अरब 1.7 प्रतिशत और वियतनाम 1.6 प्रतिशत योगदान दे सकते हैं। वहीं नाइजीरिया और ब्राजील दोनों का योगदान लगभग 1.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इस लिस्ट में जर्मनी 10वें स्थान पर है और उससे वैश्विक जीडीपी वृद्धि में 0.9 प्रतिशत योगदान का अनुमान है। इसके अलावा यूरोप के अन्य देश आईएमएफ की शीर्ष 10 सूची में शामिल नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की 2025 की आर्थिक विकास दर का अनुमान 0.7 प्रतिशत बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में आईएमएफ ने कहा कि यह संशोधन चालू वित्त वर्ष, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त होगा, की चौथी तिमाही में मजबूत आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए किया गया है। आईएमएफ के अनुसार, अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भारत उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास का प्रमुख इंजन बना रहेगा।

स्पेशल खबर भारतीय रेलवे के माल ढुलाई आय में फरवरी 2026 में 14,572 करोड़ रुपए का राजस्व जप्त

माल ढुलाई से रेलवे की कमाई बढ़ी, फरवरी में दर्ज हुई 2.97 प्रतिशत की बढ़त

नई दिल्ली । भारतीय रेलवे की माल ढुलाई से आय फरवरी में सालाना आधार पर 2.97 प्रतिशत बढ़कर 14,571.99 करोड़ रुपए हो गई है। यह जानकारी शुक्रवार को सरकार की ओर से दी गई।

पिछले वर्ष के इसी महीने में माल ढुलाई से प्राप्त आय 14,151.96 करोड़ रुपए थी।

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, इस महीने माल ढुलाई में पिछले वर्ष के फरवरी महीने के 132.48 मिलियन टन (एमटी) की तुलना में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 137.72 मिलियन टन (एमटी) हो गई।

ट्रांसपोर्ट आउटपुट, जिसे नेट टन किलोमीटर (एनटीकेएम) में मापा जाता है, फरवरी 2026 में 4.18 प्रतिशत बढ़कर 76,007 मिलियन एनटीकेएम हो गया, जो एक वर्ष पहले 72,955 मिलियन एनटीकेएम था।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस महीने माल ढुलाई मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क, तैयार इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और कंटेनर कार्गो जैसी प्रमुख वस्तुओं द्वारा संचालित थी। दैनिक माल ढुलाई में, लौह अयस्क की लोडिंग 0.529 मीट्रिक टन से बढ़कर 0.675 मीट्रिक टन हो गई (27.6 प्रतिशत की वृद्धि), जबकि कच्चा लोहा और तैयार इस्पात की लोडिंग 0.284 मीट्रिक टन से 20.8 प्रतिशत बढ़कर 0.343 मीट्रिक टन हो गई। सरकार ने यह भी बताया कि इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल (लौह अयस्क को छोड़कर) की लोडिंग 0.096 मीट्रिक टन से बढ़कर 0.141 मीट्रिक टन हो गई, जो 46.9 प्रतिशत की वृद्धि है।

मंत्रालय के अनुसार, उर्वरक की लोडिंग 10.2 प्रतिशत बढ़कर 0.184 मीट्रिक टन हो गई, जबकि खनिज तेल और कंटेनर एक्जीक्यूटिव एंड इम्पोर्ट (ईएक्सआईएम) यातायात में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मासिक संचयी आंकड़ों से प्रमुख वस्तुओं में भी मजबूत वृद्धि देखी गई। कंटेनर यातायात की बात करें तो, इस माह के दौरान आयातित माल ढुलाई में 5.6 प्रतिशत और घरेलू कंटेनर यातायात में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच, भारतीय रेलवे ने 1,503.8 मीट्रिक टन माल ढुलाई की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1,456.07 मीट्रिक टन से 3.28 प्रतिशत अधिक है। सरकार के अनुसार, इस अवधि के दौरान माल ढुलाई राजस्व 1.61 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि एनटीकेएम (न्यूनतम किलोग्राम) में मापी गई माल ढुलाई 1.62 प्रतिशत बढ़कर 840,000 मिलियन एनटीकेएम हो गई।